साभार: अनिरुद्ध सूरी

अनिरुद्ध सूरी

विदेशी मामलों में सुनहरा भविष्य

आशीष कुमार सेन द्वारा भेंटवार्ता

नई दिल्ली के अनिरुद्ध सूरी को 2006 की कारनेगी एन्डॉमेंट जूनियर फैलोशिप प्राप्त हुई है। वह वाशिंगटन थिंकटैंक में संस्थान के दक्षिण एशिया कार्यक्रम के वरिष्ठ सहयोगी और विदेश उप राज्यमंत्री निकोलस बर्न्स और भारत में पूर्व राजदूत रॉबर्ट ब्लैकविल के भूतपूर्व सलाहकार ऐशली टेलिस के साथ काम करेंगे।

पेंसिल्वैनिया के हेवरफोर्ड कॉलेज के छात्र रहे अनिरुद्ध अर्थशास्त्र और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त हैं। वहां वह वाद-विवाद और क्रिकेट की टीमों के मुखिया थे। उनकी शैक्षिक उत्कृष्टता और नेतृत्व से जुड़ी उपलब्धियों के कारण उन्हें कई सम्मान मिले। इनमें न्यूयॉर्क स्थित गोल्डमैन सैक्स फाउंडेशन का सम्मान शामिल है जिसने उन्हें वर्ष 2004 में दुनिया के 100 लीडर में चुना। सूरी इंटरनेशनल स्टूडेंट एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष हैं और उनका इरादा भारतीय विदेश सेवा में जाना है। उन्होंने स्पैन से बातचीत में कहा:

आपकी रूचि भारतीय विदेश सेवा में कैसे हुई?

हेवरफोर्ड कॉलेज में ग्रीष्मावकाश के दौरान की गई दो इंटर्नशिपों से मेरी गहरी रूचि विदेश नीति से जुड़े करिअर में बनी। पहले साल मैंने इंटर्नशिप के तहत भारत और पाकिस्तान के कश्मीर सम्बन्धी विवाद का अध्ययन किया। मैं अगली गर्मियों में कारनेगी एन्डॉमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस से जुड़ा और पाकिस्तान और भारत-चीन सैन्य संतुलन से जुड़े मुद्दों पर काम किया। मैं पिछली गर्मियों में चीन गया था, जहां मैंने पेइचिंग के एक विदेशनीति विचार समूह में भारत-चीन और अमेरिका-चीन संबंधों की दिशा की बेहतर समझदारी के लिए शोध किया।

यह सभी अनुभव बहुत प्रोत्साहित करने वाले थे और इनसे मुझे यह समझने में भी मदद मिली कि मैं सचमुच विदेश नीति के मामलों को लेकर गंभीर हूं। मैं संसार भर में विदेश नीति संबंधी फैसले और घटनाक्रम को सही परिप्रेक्ष्य में समझने-देखने लगा और अनुभव करने लगा कि भारतीय विदेश नीति को भी इसी स्तर पर पहुंचना चाहिए।

कारनेगी एंडॉमेंट में आप किन विषयों पर काम करेंगे?

भारत, पाकिस्तान और चीन के बीच सैन्य संतुलन का अध्ययन, एशिया में मिसाइल सुरक्षा की भूमिका, पाकिस्तान में लोकतंत्रीकरण और विसैन्यीकरण, ईरान मुद्दा, भारत-अमेरिकी रणनीतिक सम्बन्ध, भारत-चीन और भारत-पाकिस्तान सम्बन्ध। मैं ऐशली टेलिस के साथ भारत-अमेरिकी रणनीतिक सम्बन्धों पर काम करूंगा और इस पर रिर्पोट भी लिखूंगा। हाल ही में हुए भारत-अमेरिका परमाणु समझौते में ऐशली टेलिस की महत्वपूर्ण भूमिका थी।

किन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भारत-अमेरिकी सम्बन्ध बढ़े हैं?

परमाणु समझौते के अलावा वस्तुओं और सेवाओं के द्विपक्षीय व्यापार के मामले में भी भारत-अमेरिकी सम्बन्धों में वृद्धि हो रही है। दोनों देशों के बीच व्यापार फल-फूल रहा है और दोनों देशों की कम्पनियां इस अवसर का लाभ उठाते हुए दूसरे देश में अपना व्यापार स्थापित कर रही हैं या बढ़ा रही हैं। भारत का मध्य वर्ग बढ़ रहा है और अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए वह बहुत बढ़िया उभरती मंडी है। उधर अमेरिका का विकसित बाजार इन्फोसिस, रिलायंस, टाटा, टीसीएस, विप्रो जैसी बड़ी भारतीय कंपनियों के लिए बढ़िया जगह है। कई कंपनियों ने भारत में शोध और विकास केंद्र भी खोले हैं और यह काम यहां बढ़िया चल रहा है। मुझे विश्वास है कि परमाणु समझौते के बाद दोनों के बीच अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न विषयों जैसे संयुक्त राष्ट्र में सुधार, उग्रवाद से मुकाबला आदि पर भी सहयोग बढ़ेगा।

समस्या के क्षेत्र कौन से हैं?

अब भी व्यापार के कई मुद्दों पर भारत और अमेरिका सहमत नहीं हैं। कृषि के क्षेत्र में भारत और अधिक छूट की मांग कर रहा है जबकि अमेरिका भारत से उदारीकरण की प्रक्रिया तेज करने, मूल्य और कम करने और अपने बाजार पूरी तरह खोल देने का आग्रह कर रहा है। मुझे लगता है कि यह समस्या का बड़ा क्षेत्र है हालांकि दोनों पक्षों के नेता यह मान चुके हैं कि इस मुद्दे को परस्पर द्विपक्षीय हित के अन्य क्षेत्रों में प्रगति में बाधक नहीं बनना चाहिए।

भारत उस आतंकवाद के विरुद्ध अपने युद्ध के लिए अधिक मान्यता चाहता है जो उसके अनुसार सीमापार से प्रोत्साहन पा रहा है। लेकिन अमेरिका पाकिस्तान के विरुद्ध कड़ा कदम उठाने में हिचकिचा रहा है क्योंकि वह आंतकवाद के खिलाफ अमेरिका से सहयोग कर रहा है। लेकिन अमेरिका राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ से लगातार पाकिस्तान में उपस्थित आंतकवादी समूहों के खिलाफ समुचित कार्रवाई करने का आग्रह करता रहा है।

विदेशी पूंजी निवेश के क्षेत्र में चीन के बराबर पहुंचने के लिए भारत को क्या करना चाहिए?

यह तो एकदम ही जाहिर है कि सबसे पहले तो भारत को आधारभूत ढांचों के क्षेत्र में सुधार लाना होगा। इसके अलावा निर्णय लेने की प्रक्रिया को बाधामुक्त बनाना होगा और नीति संबंधी निर्णय ले लेने के बाद उसके कार्यान्वयन में आने वाली बड़ी बाधाओं को आने से रोकना भी सीखना होगा। भारत को लालफीताशाही कम करनी होगी। मैं अमर्त्य सेन से पूरी तरह सहमत हूं जो मानते हैं कि प्राथमिक शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में सही निर्णय लिए बिना भारत चीन की बराबरी नहीं कर सकता। □

आशीष कुमार सेन वाशिंगटन में रहते हैं। वह वाशिंगटन टाइम्स, द ट्रिब्यून और आउटलुक के लिए लिखते हैं।